SHRI HARDEEP SINGH PURI: The proposal from the Government of Odisha for a rapid rail transport system from Bhubaneswar onwards and all other proposals are being examined. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: These disruptions are not going on record. ...*(Interruptions)*...

SHRI HARDEEP SINGH PURI: I will communicate...*(Interruptions)*... These proposals are being examined. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN : Q.No. 257

दिल्ली में दंगा पीड़ितों के लिए राहत और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान किया जाना

*257. **चौधरी सुखराम सिंह यादव**: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फरवरी, 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के पीड़ितों के लिए राहत तथा अन्य प्रकार की सहायता हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं;

(ख) दंगों की जांच में अभी तक जो जानकारी सामने आई है, उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दंगों में संलिप्त व्यक्तियों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उत्तर पूर्वी और शाहदरा जिलों के दंगा प्रभावित क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए राहत और पुनर्वास प्रयासों में अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न मामलों में अनुग्रहपूर्वक राहत प्रदान करना; दंगों के दौरान आवासीय इकाइयों को हुए नुकसान के लिए मुआवजा; सीडीएमओ, बीडीओ और जिलों की नागरिक एजेंसियों यथा दिल्ली जल बोर्ड, पुलिस, ईडीएमसी आदि के साथ मिलकर बिस्तर, कंबल, दवाइयां, भोजन, साफ-सफाई और स्वच्छ पेयजल सहित मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना; मेडिको-लीगल प्रमाणपत्र और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने के लिए जीटीबी अस्पताल, एलएनजेपी अस्पताल और जग प्रवेश चंद्र अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षकों का नोडल अधिकारी के रूप में नामांकन करना; सीएटीएस द्वारा 14 एम्बुलेंस प्रदान करना; और सभी कॉलों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए अग्निशमन विभाग को निर्देश जारी करना शामिल हैं। जिलों में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं के मद्देनजर शुरू किये जाने वाले राहत, पुनर्वास, सहायता और किसी भी अन्य गतिविधियों के समन्वय कार्य और इन्हें सुविधाजनक बनाने के लिए दिल्ली सरकार के सचिव

स्तर के छः अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। सब-डिवीज़नल मजिस्ट्रेटों से कहा गया है कि वे बिस्तर, कंबल, दवाई, भोजन, साफ-सफाई और स्वच्छ पेयजल सहित मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करें। दिल्ली पुलिस ने भी हिंसा से प्रभावित लोगों को चिकित्सा देखभाल सुलभ कराने की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ई.डी.एम.सी.) ने स्वच्छता सेवाओं की बहाली करने; मलबे और जले हुए अवशेषों को हटाने; और क्षतिग्रस्त सड़कों पर विशेष पानी के छिड़काव करने सहित दंगा प्रभावित क्षेत्र में सामान्य स्थिति को बहाल करने के लिए त्वरित कार्रवाई की है।

(ख) और (ग) दिल्ली पुलिस द्वारा सूचित किए अनुसार, दिनांक 12.03.2020 की स्थितिनुसार, आयुध अधिनियम के तहत 51 मामलों सहित 763 मामले दर्ज किए गए हैं और 3,304 व्यक्तियों को गिरफ्तार/डिटेन किया गया है। 48 हथियार बरामद किए गए हैं। मामलों की व्यापक और कारगर जांच करने के लिए अपराध शाखा के डी.सी.पी. स्तर के अधिकारियों की देखरेख में अपराध शाखा की दो विशेष जांच टीमें (एस.आई.टी.) गठित की गई हैं। दोषियों को गिरफ्तार करने और सबूत जुटाने के लिए 40 टीमों का गठन किया गया है।

Relief and other assistance for victims of riots in Delhi

†*257. CH. SUKHRAM SINGH YADAV: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the steps taken by Government for the relief and other assistance to the victims of the riots taken place in Delhi in February, 2020;

(b) the details of the information revealed, so far, in the investigation of the riots; and

(c) the details of action taken against the people involved in these riots?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI G. KISHAN REDDY): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) As informed by the Government of NCT of Delhi, the relief and rehabilitation efforts taken by them in the riot affected areas of North East and Shahdara Districts, *Inter-alia*, include grant of *ex-gratia* relief in various eventualities; compensation for damage to residential units during the riots; ensure the availability of basic amenities including bedding, blankets, medicines, food, sanitation and clean drinking water in

†Original notice of the question was received in Hindi.

association with the CDMOs, BDOs and civic agencies like DJB, Police, EDMC etc. of the districts; nomination of the Medical Superintendents of GTB Hospital, LNJP Hospital and Jag Pravesh Chandra Hospital as Nodal Officers for preparation of medico-legal certificates and post-mortem reports; providing 14 ambulances by CATs; and issuing direction to Fire Department to take quick action on all the calls. Six Secretary level officers of Delhi Government have been deputed in the Districts to coordinate and facilitate the relief, rehabilitation, support and any other activities that are to be undertaken in the wake of the recent violent incidents in the districts. Sub-Divisional Magistrates have been asked to ensure the availability of basic amenities including bedding, blankets, medicines, food, sanitation and clean drinking water, etc. Delhi Police has also played a vital role in providing assistance to people affected by violence in accessing medical attention.

East Delhi Municipal Corporation (EDMC) took prompt action to restore normalcy in the riot affected area including restoration of sanitation services; clearing debris and fire remains; and special water sprinkling on the damaged roads.

(b) and (c) As reported by Delhi Police, as on 12.03.2020, 763 cases including 51 cases under Arms Act have been registered and 3,304 persons have been arrested/ detained. 48 arms have been recovered. Two Special Investigation Teams (SIT) of Crime Branch have been constituted under the supervision of DCP level officers of Crime Branch for comprehensive and effective investigation of cases. 40 teams have been constituted to arrest culprits and collect evidence.

चौधरी सुखराम सिंह यादव: माननीय सभापति जी, दिल्ली की जो घटना हुई, मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: As you all know, इस तरह से नहीं चलेगा in the House. I am adjourning the House to meet at 2.00 p.m.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Eviction/rehabilitation of slums for Metro projects

*258. SHRI NARAIN DASS GUPTA: Will the Minister of HOUSING AND URBAN AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that slums/squatters/JJ colonies are resettled/rehabilitated/ evicted for the construction of Metro in different Metro projects in cities;